सनातन संस्कृति को मजबूत करने में संत और महात्माओं का अद्वितीय योगदान : मुख्यमंत्री

'युवा पीढ़ी संतों की शिक्षा आत्मसात करें, भारत की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ाएं'

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर के आराध्य श्री गोविंददेव जी मंदिर परिसर स्थित जय निवास उद्यान से विधिवत पूजा-अर्चना कर विशाल कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत-महात्मा राष्ट्र को सही दिशा देकर सनातन संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं तथा इनके विचार मानवता, सेवा एवं सद्भावना का संदेश देते हैं।

उन्होंने युवाओं से आव्हान किया कि संतों की शिक्षाओं और आदर्शों को आत्मसात करें तथा भारत की गौरवाशाली परम्परा को आगे बढ़ाने में योगदान दें। शर्मा ने कहा कि बाबा बालनाथ ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने में अद्वितीय योगदान दिया। इसी परंपरा का बाबा बस्तीनाथ जी महाराज भी अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की अवधारणा पर आधारित है, जो सम्पूर्ण मानवता के कल्याण का संदेश देती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बस्तीनाथ महाराज को दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान शर्मा ने महाराज जी के आशीर्वचन भी सुनें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर परिसर से विशाल कलश यात्रा का शुभारंभ किया।

- मुख्यमंत्री ने गोविंददेवजी मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि के लिए कामना की

कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इससे पहले शर्मा ने गोविंददेव जी मंदिर में दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की तथा प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। उन्होंने मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं से आत्मीयता के साथ मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने भगवान गोविंददेव जी के जयघोष से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर विधायक देवी सिंह शेखावत सहित लोग और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

पं. उपाध्याय की पुण्यतिथि आज

जयपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति द्वारा एकात्म मानववाद के प्रणेता पं. दीन दयाल उपाध्याय की 58 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृति में पुष्पांजलि एवं प्रार्थना सभा का आयोजन बुधवार को सायं 4 बजे से 5:30 बजे तक धानक्या रेलवे स्टेशन स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक स्थल पर किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष प्रो. मोहनलाल छीपा ने बताया कि पुण्यतिथि पर हर वर्ष की भांति 11 फरवरी को धानक्या में दीनदयाल जी के राष्ट्रीय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए प्रार्थना सभा रखी है। पुण्यतिथि के अवसर पर भण्डारी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, जयपुर एवं समिति के सहयोग से स्मारक पर प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निःशुल्क चिकिसा शिविर लगेगा, जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद एवं योग चिकित्सा के विशेषज्ञ जाँच कर परामर्श प्रदान करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाधयाय के जीवन से सम्बंधित दुर्लभ छायाचित्र और प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा।

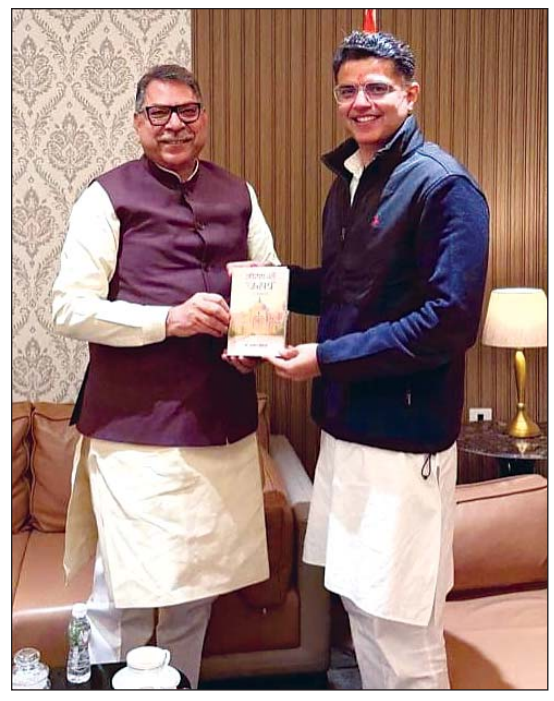

राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने जयपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट से मुलाकात के दौरान ''अग्निपथ नहीं जनपथ'' पुस्तक भेंट की।

'दिहाड़ी मजदूर की महीने की आय 26 नहीं 30 दिनों की मानी जानी चाहिए'

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना के मुआवजे से जुड़े मामले में कहा कि दिहाड़ी मजदूर की महीने की आय 26 दिनों के बजाय 30 दिनों की मानी जानी चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने अफसरों को 26 दिनों के बजाय 30 दिनों की मजदूरी की गणना करने का निर्देश दिया है, जिससे संबंधित पक्षकारों को सही मुआवजा मिल सके।

अदालत ने आदेश की कॉपी केन्द्र सरकार के श्रम मंत्रालय सचिव, श्रम विभाग व राज्य सरकार को भी भेजने का निर्देश दिया है, ताकि वे दिहाड़ी मजदूरों को महीने में 26 दिन के बजाय 30 दिन की न्यूनतम मजदूरी देने के अपने नोटिफिकेशन को बदलने के लिए कदम उठाए।

जस्टिस अनूप कुमार यह आदेश लक्ष्मण कुमावत की अपील को मंजूर करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि प्रार्थी मुआवजे के तौर पर 33040 रुपए की अतिरिक्त राशि और प्राप्त करने का हकदार है।

ऐसे में मामले से जुड़े संबंधित पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे मजदूरी की पुनः गणना कर बढ़ी हुई राशि दो महीने में प्रार्थी को याचिका दायर करने की तारीख से 6 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करें। अपील में अधिवक्ता राहुल सिंह ने कहा कि अपीलार्थी 27 अगस्त, 2020 को मोटरसाइकिल से जा रहा था। इतने में दूसरी तरफ से वाहन ने आकर उसे टक्कर मार दी।

जिससे उसके गंभीर चोटें आई। इस पर अपीलार्थी की ओर से स्थानीय एमएसीटी कोर्ट में मुआवजे के लिए परिवाद पेश किया गया। जिस पर फैसला देते हुए अधिकरण ने मुआवजे की गणना के लिए न्यूनतम मजदूरी की गणना 26 दिनों से की। जबकि दैनिक मजदूर को माह में 30 दिन काम करने वाला माना जाता है।

इसलिए मुआवजे की गणना तीस दिन मजदूरी के आधार पर किया जाए। जिसका विरोध करते हुए बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि श्रम मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मजदूर माह में 26 दिन ही काम करते हैं।

ऐसे में अधिकरण ने अपने आदेश में कोई गलती नहीं की है। इसलिए अपील को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मजदूरी की गणना तीस दिन के आधार पर करने को कहा है।

'धार्मिक स्थलों में भक्तों के लिए सुरक्षा और संसाधन मुहैया कराए'

जयपुर (कासं)। राज्य मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि धार्मिक स्थलों पर लाखों की संख्या में आने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इनकी अनदेखी से ही पूर्व में विभिन्न मंदिरों और दरगाहों में अव्यवस्थाओं के चलते, भगदड़ जैसी दुखद घटनाओं में दर्शनार्थियों ने अपनी जान खोयी है और कई घायल भी हुए हैं। ऐसे में देवस्थान विभाग और मुख्य धार्मिक स्थलों से संचालक मंडलों से आयोग अपेक्षा करता है कि वे धार्मिक स्थलों में उचित संसाधन सुनिश्चित करें। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश प्रकरण में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए।

आयोग ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर पीने के पानी, छाया, बैठने के लिए स्थान, वृद्ध, बीमार और महिलाओं के लिए अलग पंक्ति के साथ ही सुलभ दर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही आयोग ने देवस्थान आयुक्त को कहा है कि वे धार्मिक स्थलों में इन सुविधाओं को लेकर आयोग में रिपोर्ट पेश करें।

आयोग ने मामले में प्रदेश में प्रमुख मंदिरों के प्रबंधकों के साथ ही सभी संभागीय आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किए हैं।

आयोग ने रामदेवरा, श्रीनाथजी, सांवरिया सेठ, खाटू श्याम जी, मेहंदीपुर बालाजी, गोविन्द देवजी, सालासर बालाजी, बेणेश्वर धाम, चौथ माता, मोती डूंगरी, एकेश्वर, गलता, गोवर्धन जी, जोधपुर का रामदेवरा, पाल के बालाजी, संतोषी माता, रातानाडा गणेश मंदिर और अजमेर दरगाह के साथ ही किलों में स्थित माताजी के मंदिर साल में कई बार मेले भरते हैं। जिसके लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। असंख्य जनसमूह के एकत्र होने पर भगदड जैसी घटनाएं भी हुई हैं।

राजस्थान में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण की सेवाएं मजबूत करेगी सरकार

पारदर्शिता के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन संचालित किया जाएगा : गायत्री राठौड़

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में समीक्षा बैठक ली।

जयपुर (कासं)। प्रदेश में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण सेवाओं को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के लिए प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन संचालित किया जाएगा। इसके लिए नव विकसित लाइव पोर्टल जल्द शुरू किया जाएगा। अंगदान एवं प्रत्यारोपण करने वाले सभी अस्पतालों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि अंगदान एवं प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और सभी जानकारियां इस पर उपलब्ध हों।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड ने स्वास्थ्य भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण जीवन रक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश में इससे जुड़ी सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मानक प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने के साथ ही विजिलेंस सिस्टम को सुदृढ़ बनाया जाएगा। राठौड़ ने कहा कि अंगदान एवं प्रत्यारोपण के कार्यों के लिए निदेशालय स्तर पर गठित प्रकोष्ठ को और सुदृढ़ किया जाएगा।

यह प्रकोष्ठ नियमित रूप से अस्पतालों का निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अस्पतालों में अंगदान एवं प्रत्यारोपण की प्रक्रियाएं एसओपी के अनुरूप हों और उन अस्पतालों में इन कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। साथ ही,सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पोर्टल पर अपडेट हों।

- लाइव पोर्टल से जुड़ेंगे सभी अस्पताल, विजिलेंस सिस्टम भी मजबूत होगा

सीएचसी स्तर तक मिलेगा प्रशिक्षण

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए मेडिकल कॉलेज से लेकर ट्रोमा सेंटर एवं सीएचसी स्तर तक स्वास्थ्यकर्मियों एवं एम्बुलेंसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही, आमजन एवं स्वास्थ्यकर्मियों में इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूकता बढाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

जनसमस्या निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वे जनसमस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जनसुनवाई, सम्पर्क पोर्टल, 181 हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री कार्यालय या अन्य माध्यमों से प्राप्त परिवेदनाओं का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही, शिकायतकर्ता से बात कर समस्या समाधान का फीडबैक भी प्राप्त करें। उन्होंने ग्रिवांस रिडरेसल सिस्टम को मजबूत बनाने और इसके लिए तकनीकी नवाचारों को अपनाने पर भी बल दिया।

बेहतर सर्विस डिलीवरी पर फोकस

राठौड़ ने कहा कि अधिकारी स्वयं के स्टाफ की समस्याओं का भी समय पर निस्तारण कर उन्हें राहत प्रदान करें। कार्यालय परिसर में साफ-सफाई, रंग-रोगन एवं नियमित मेंटीनेंस के कार्यों पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कार्मिक बेहतर सर्विस डिलीवरी पर फोकस करते हुए आमजन को विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों का पूरा लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव, अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निधि पटेल, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त नरेश गोयल, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पीएम सेतु योजना में राजस्थान देशभर में नंबर-1 बना

''राजस्थान इकलौता राज्य है, जिसे भारत सरकार के कौशल मंत्रालय के राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर सभी ग्रीन इंडिकेटर प्राप्त है।''

जयपुर। प्रधानमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार क्षमता उन्नयन (पीएम-सेतु) योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में नंबर-1 स्थान पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कौशल विकास और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसके लिए वर्ष 2025 में नई कौशल नीति तथा जनवरी-2026 में रोजगार नीति लागू की गई।

ज्ञात रहे कि पीएम-सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी आईटीआई को आधुनिक बनाना, इंडस्ट्री-लिंक्ड ट्रेनिंग प्रदान करना और कौशल विकास द्वारा रोजगार बढ़ाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ स्वयं राज्य के आई.टी.आई. कलस्टरों की पहचान व उन्नयन के लिए प्रयासरत है।

मंत्री राठौड़ ने बताया कि राजस्थान सरकार के कौशल, रोजगार व उद्यमिता विभाग ने इस पी.पी.पी. योजना के टैंडर दस्तावेज तैयार करते समय व्यापक सुधार किए है। राज्य द्वारा ''रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आर.पी.एफ.) जारी की है, जिसे भारत सरकार की मॉडल आर.पी.एफ. के अनुरूप रखते हुए पिछले 3 महीनों में हितधारक परामर्श बैठकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर और अधिक व्यवहारिक बनाया है। इन सुधारों का उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। मंत्री राठौड़ ने बताया कि राजस्थान, देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसे भारत सरकार के कौशल मंत्रालय के राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर सभी ग्रीन इंडिकेटर प्राप्त है। यह सरकार की कार्यशैली दर्शाता है।

मंत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार ने इस योजना में एक प्रमुख सुधार करते हुए 10 वर्ष का अनुबंध अवधि तय की है, जिसमें योजना का वित्त पोषण केवल 5 वर्ष तक होगा। इससे 9 पूर्ण शैक्षणिक चक्रों का संचालन संभव होगा और अल्पकालिक परियोजनाओं से जुड़ी अस्थिरता में कमी आएगी। मंत्री राठौड़ ने बताया कि 16 फरवरी को बोलीदाताओं और हितधारकों के लिए विशेष कार्यशाला होगी, जिसमें ''रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आर.पी.एफ.) की बारीकियां, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और रणनीतिपूर्ण निवेश प्लान बनाने के बारे में मार्गदर्शन दिया जायेगा।

योजना के तहत प्री-बिड मीटिंग 4 मार्च 2026 को प्रस्तावित है, जिसमें संभावित बोलीदाताओं को टैंडर दस्तावेजों का अध्ययन करके सुझाव व शंकाए प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा।

वन संपदा संरक्षण और इंसानों व वन्यजीवों का संघर्ष रोकने के लिए सरकार गंभीर

वन मंत्री ने वाइल्डलाइफ इंटेलिजेंस नेटवर्क सशक्त बनाने तथा संरक्षित वन क्षेत्रों में वन्यजीवों की समुचित निगरानी के लिए विशेष सेल बनाने के निर्देश दिए

जयपुर (कासं)। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में राज्य वन्यजीव मंडल की स्थायी समिति की सप्तम बैठक हुई। संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की वन्यजीव संपदा के संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में सतत और प्रभावी कदम उठा रही है।

वन मंत्री ने वाइल्डलाइफ इंटेलिजेंस नेटवर्क को सशक्त बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे वन्यजीव संबंधी मामलों में वन विभाग की पुलिस पर निर्भरता कम होगी। वन्यजीवों के जनसंख्या प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। किसी वन्यजीव की मृत्यु की स्थिति में विभाग द्वारा प्रेस वार्ता कर तथ्यात्मक जानकारी साझा की जाए, ताकि भ्रामक और अपुष्ट खबरों से आमजन को दूर रखा जा सके।

उन्होंने फॉरेस्ट कम्युनिटी डवलपमेंट प्रोग्राम संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे वन क्षेत्रों में निवासरत समुदायों को आजीविका के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। बैठक में कराकल संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई तथा वन्यजीव संरक्षण की दिशा में भावी कार्ययोजना पर सुझाव आमंत्रित किए गए।

वन मंत्री संजय शर्मा ने मंगलवार को सचिवालय में राज्य वन्यजीव मंडल स्थायी समिति की बैठक ली।

वन राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि संरक्षित वन क्षेत्रों में वन्यजीवों की समुचित निगरानी के लिए एक विशेष सेल का गठन किया जाए, जो नियमित रूप से विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में स्थित ऐतिहासिक महत्व की इमारतों, स्मारकों एवं शिकार हॉल का विभाग द्वारा समुचित संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इन स्थलों का चिन्हांकन कर उन्हें पर्यटन की दृष्टि से व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने कहा कि वन्यजीव की मृत्यु के बाद विभागीय स्तर पर स्पष्ट प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाए। साथ ही, वन क्षेत्रों से सटे गांवों में प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित किया जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाएं और आवश्यक समाधान सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में 7 नवंबर को आयोजित पिछली बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया तथा प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही वन्यजीव स्वीकृति से जुड़े नए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें संरक्षित वन क्षेत्रों में सड़कों के नवीनीकरण, विद्युत लाइनों के संचालन तथा सामुदायिक सहभागिता से संबंधित महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे।

- वन्यजीव की मृत्यु पर तथ्यात्मक जानकारी प्रेस वार्ता के जरिए साझा करें, ताकि लोगों को भ्रामक और अपुष्ट खबरों से दूर रखा जा सके
- उन्होंने वन क्षेत्रों में स्थित ऐतिहासिक महत्व की इमारतों, स्मारकों एवं शिकार हॉल का समुचित संरक्षण करने तथा इन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के निर्देश दिए

बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख पवन कुमार उपाध्याय, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के.सी.ए. अरुण प्रसाद, समिति के सदस्य डॉ. रवि सिंह, राजपाल सिंह तंवर, निरंजन कुमार वसु, नम्रता भारतीय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने किया लोक कला संगम के पोस्टर का विमोचन

जयपुर। राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से होने वाले लोक कला संगम-2026 का शुभारंभ राजभवन में हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इस त्रि-दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव के पोस्टर का विधिवत विमोचन किया। राज्यपाल बागडे ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे लोक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। संस्कार भारती, राजस्थान सरकार के पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग तथा जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन 20 से 22 फरवरी 2026 तक शिल्पग्राम, जयपुर में आयोजित किया जाएगा।

संस्कार भारती के प्रांत मंत्री प्रदीप सिंह राजावत ने बताया कि आयोजन की थीम ''राजस्थान रै लोकरंग रो उजास है'', जिसके अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए 400 से अधिक लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। संस्कार भारती के प्रांत महामंत्री बनवारी लाल चेजारा ने कहा कि लोक कला संगम-2026 केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि लुप्तप्राय लोक कलाओं के पुनर्जीवन और कलाकारों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का एक सशक्त सांस्कृतिक अभियान है।

पुरानी घोषणाएं धूल फांक रहीं, बुधवार को फिर होगी जुमलों की बौछार : जूली

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को राज्य बजट पेश होगा, लेकिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इससे पूर्व ही सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है। एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए जूली ने कहा कि हमने सरकार के पिछले वादों का रियलिटी चैक किया और वर्तमान शासन को ''विकास विरोधी व हैडलाइन प्रेमी'' पाया। उन्होंने कहा कि 26 प्रतिशत कार्यों को अब तक हाथ भी नहीं लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कुल घोषणाएं: 2717 हुई, जिनमें पूर्ण कार्य: मात्र 754 हुए। शून्य प्रगति: 707 घोषणाएं (26.02 प्रशित) ऐसी हैं जिन्हें सरकार ने दो साल बीतने के बावजूद छुआ तक नहीं है। जूली ने सवाल तंज कसते हुए कहा कि ''जब पिछली घोषणाओं का धरातल पर अस्तित्व ही नहीं है, तो नए बजट का क्या औचित्य? यह बजट प्रदेश के विकास का दस्तावेज नहीं, बल्कि भाजपा की विफलता को छिपाने का आंकडों वाला पर्दा होगा।''

जूली ने कहा कि जयपुर के सिविल लाइन्स का फ्लाईओवर आज भी अधूरा है, जबकि इसी मार्ग से मुख्यमंत्री का काफिला प्रतिदिन गुजरता है। जो सरकार अपनी आंखों के सामने चल रहे प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं करा सकती, वह प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में विकास क्या खाक करेगी? सहकार मार्ग फ्लाईओवर की घोषणा तो केवल कागजी पुल बनकर रह गई है।''

- नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा के बजट को केवल आंकड़ों का मायाजाल बताया

जूली ने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की लेटलतीफी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने इसे बीरबल की खिड़ी बना दिया है। दिसंबर 2024 की डेडलाइन को बढ़ाकर अगस्त 2025 किया गया, लेकिन आज फरवरी 2026 तक भी लोकार्पण का कोई अता-पता नहीं है। 2024 में प्रदेश को 1000 इलेक्ट्रिक बसें देने का वादा किया गया था। दो साल बीत गए, लेकिन सड़कों पर एक भी नई बस नहीं उतरी।

जनता आज भी धुआं उगलती खटारा बसों में सफर को मजबूर है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बुधवार को सदन में पेश होने वाला बजट भी लुभावने जुमलों और झूठी उम्मीदों का अंबार होगा। सरकार अपनी परफॉरमेंस रिपोर्ट को छिपाने के लिए फिर से भारी-भरकम शब्दजाल बुनेगी।